

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 781/2023

में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15025/2022

- राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।

-----अपीलार्थीगण

बनाम

सुखेंद्र प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम साबुनिया पोस्ट जैतपुर, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर। वर्तमान में निवासी सी/ओ उमा राम जाखड़, ग्राम करंगा बड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)।

-----प्रतिवादी

अपीलार्थी(ओं) के लिए : सुश्री प्रत्युषी मेहता, अधिवक्ता
श्री कपिल प्रकाश माथुर, अतिरिक्त
महाधिवक्ता की ओर से।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : सुश्री शिखा परनामी, अधिवक्ता।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

16/07/2024

1. अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए प्रार्थना पर सुनवाई हुई।
2. आवेदन में दिखाए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, हम अपील दायर करने में देरी को माफ करने के इच्छुक हैं। तदनुसार, देरी को माफ किया जाता है।
3. आवेदन संख्या 311/2023 स्वीकार किया जाता है। पार्टियों की सहमति से अपील को अंतिम रूप से सुना जाता है।
4. इस अंतः न्यायालय अपील द्वारा, राज्य ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 28.03.2023 के आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया है।
5. इस अपील में शामिल विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पंचायती राज विभाग ने राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 12.02.2013 को एक विज्ञापन जारी किया। भर्ती एजेंसी ने विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का भी प्रावधान किया। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.03.2013 थी। विज्ञापन ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (इसके बाद '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित) के

नियम 273 के तहत निर्धारित एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित किया, जो इस प्रकार है:-

"नियम 273. लिखित परीक्षा।- समिति [डाइवरों, चतुर्थ श्रेणी और धारा 89 की उप-धारा 2 के खंड (iii) में निर्दिष्ट पदों को छोड़कर] सभी श्रेणियों के [पदों] के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है। [परीक्षा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। (हटाया गया) डी.ई.सी. ऐसे आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगा:

[परंतु हटाया गया]

[यह भी प्रावधान है कि अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे भारांक और एक वर्ष से अधिक के अनुभव की लंबाई को ध्यान में रखते हुए राज्य में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मनरेगा या किसी अन्य योजना में प्लेसमेंट एजेंसी के अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (जे.टी.ए.), जूनियर इंजीनियर, ग्राम रोजगार सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, लेखा सहायक, अवर श्रेणी लिपिक, कोऑर्डिनेटर 1 ईसी, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन के पद पर लगे व्यक्तियों द्वारा अर्जित किए गए ऐसे अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- जहां किसी विशेष परीक्षा में उम्मीदवार को दिए गए ग्रेड के कारण अंकों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऐसी परीक्षा में उम्मीदवार को दिए गए ग्रेड का माध्य मेरिट सूची तैयार करने का आधार होगा।]

[यह भी प्रावधान है कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे भारांक और एक वर्ष से अधिक के अनुभव की लंबाई को ध्यान में रखते हुए राज्य में मनरेगा योजना में सहायक (सहायक कर्मचारी) के पद पर लगे व्यक्तियों द्वारा अर्जित किए गए ऐसे अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।]

6. न्यूनतम पात्रता मानदंड में सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शामिल थी। रिट याचिका में जो कहा गया था और तथ्यों पर विवादित नहीं था, वह यह था कि हालांकि 1996 के नियमों और विज्ञापन के तहत निर्धारित शैक्षणिक पात्रता मानदंड सीनियर सेकेंडरी था, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल) के साथ 10 वीं पास की योग्यता रखता था।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने खुद को समकक्षता के दावे पर योग्य मानते हुए अपने उम्मीदवारी पर विचार के लिए एक आवेदन पत्र जमा किया, हालांकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिस्से के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था, और न ही भर्ती के प्रयोजनों के लिए दो योग्यताओं के बीच समकक्षता को दर्शाने वाला कोई आदेश मौजूद था। हालांकि, भर्ती की प्रक्रिया जारी रही और समाप्त नहीं हो सकी। 12.10.2015 को, राजस्थान सरकार (स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा कुछ योग्यताओं को 12 वीं पास के समकक्ष घोषित किया गया था। इस आदेश के अनुसार, वे, जिन्होंने 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन साल का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम किया था, जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने के प्रयोजनों के लिए पात्र होंगे और उन योग्यताओं को 12 वीं पास के समकक्ष माना जाएगा।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उम्मीदवारी अपीलार्थीगण के पास लंबित रही क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया एक

लंबी अवधि तक अनिर्णायक रही जब तक कि अपीलार्थीगण ने वर्ष 2022 में एक अनंतिम चयन सूची जारी नहीं की। जैसा कि राज्य के जवाब से पता चलता है, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के दस्तावेजों के सत्यापन के समय, यह पाया गया कि उसने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए, उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया। चूंकि चयन की प्रक्रिया जारी थी और उम्मीदवारी की अस्वीकृति वर्ष 2022 में हुई थी, इसलिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने अपनी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के अपीलार्थीगण के कार्य को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को पात्रता मानदंड योग्यता नहीं रखने के अलावा, उसे कार्य अनुभव का पात्रता मानदंड भी नहीं रखने के रूप में माना गया था। उपर्युक्त निर्णय को चुनौती दिए जाने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने, पार्टियों के अभिवचनों और उसके समक्ष तथ्यों के आधार पर, यह विचार किया कि 12.10.2015 को योग्यता की एक समकक्षता खींची गई थी, जिसे योग्य माना गया है। नतीजतन, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

9. इस अपील में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की शुद्धता और वैधता पर हमला करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने विस्तार से तर्क दिया और प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश कानून और तथ्य की बड़ी गलती में पड़ गए क्योंकि उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, यानी 22.03.2013 को, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के पास पात्रता मानदंड नहीं था और यह केवल 12.10.2015 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए बाद के आदेश के कारण था जिसे आधार बनाया गया, राहत दी गई जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि भर्ती

की प्रक्रिया में एक उम्मीदवार की पात्रता को नियमों या विज्ञापन में निर्धारित तिथि पर या उसके अभाव में, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर उम्मीदवार द्वारा रखी गई योग्यता के आधार पर आंका जाना है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 22.03.2013 को या उससे पहले योग्यता की पात्रता मानदंड रखने की आवश्यकता थी और समकक्षता की बाद की अधिसूचना/आदेश उसे भर्ती के प्रयोजनों के लिए, बहुत कम 22.03.2013 को, पात्र नहीं बनाएगा।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह सराहना नहीं की कि 12.10.2015 के आदेश के माध्यम से खींची गई सीमित समकक्षता का उद्देश्य और प्रयोजन उन लोगों को उच्च शिक्षा के रास्ते प्रदान करना था जिन्होंने 10 वीं पास की थी, लेकिन उसके बाद, सीनियर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बजाय पॉलिटेक्निक कोर्स और अन्य प्रकार के कोर्स किए थे। योग्यता की समकक्षता का दायरा और आयाम केवल उच्च शिक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रवेश और रास्ते को सुविधाजनक बनाने के लिए है और इसलिए, इसे भर्ती के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा दिया गया तीसरा तर्क, जो एक वैकल्पिक तर्क की प्रकृति में अधिक है, यह है कि भले ही यह मान लिया जाए कि 12.10.2015 के आदेश को भर्ती के प्रयोजनों के लिए भी लागू किया जा सकता है, आदेश/अधिसूचना का पाठ और प्रवृत्ति दिखाती है कि इसका मतलब केवल भविष्यलक्षी था और भूतलक्षी नहीं था क्योंकि यह स्पष्ट करने वाला नहीं था, बल्कि कुछ उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाने के

लिए लिए गए एक नीतिगत निर्णय की प्रकृति में अधिक था। इसलिए, यह केवल भविष्यलक्षी था और किसी भी मामले में, इसे 12.10.2015 के आदेश से पहले शुरू की गई चयन की प्रक्रिया में पात्रता का दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

12. अपीलार्थीगण के विद्वान वकील का चौथा तर्क यह है कि भले ही यह माना जाता कि तीन साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स भर्ती के प्रयोजनों के लिए भी समकक्ष माना जाता है, तो एकमात्र रास्ता यह था कि 12.10.2015 के आदेश के आधार पर योग्य बनने वाले सभी लोगों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए, न कि उन लोगों को लाभ देने के लिए जिन्होंने 12.10.2015 के आदेश के माध्यम से समकक्षता की घोषणा से पहले आवेदन किया था। इस तरह का चयनात्मक उपचार अनुचित होगा और उम्मीदवारों को आकस्मिक परिस्थितियों पर लाभ देगा, न कि एक घोषित पात्रता मानदंड के आधार पर जो एलडीसी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए समान मानदंड रखने वाले अन्य सभी उम्मीदवारों को अवसर देगा।

13. अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती) बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य, 1993 सप्ली. (3) सुप्रीम कोर्ट केसेस 168, जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि और अन्य बनाम आर्य के. बाबू और अन्य, (2019) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 587 और अंकिता ठाकुर और अन्य बनाम एच.पी. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1472 के मामलों में भरोसा किया है।

14. इसके विपरीत, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के समर्थन में, जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने समकक्षता को आधार बनाया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खींची गई किसी भी समकक्षता के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं राज्य द्वारा 12.10.2015 को जारी किए गए एक समकक्षता आदेश के आधार पर पात्रता मानदंड रखता था। वह तर्क देगी कि आदेश प्रकृति में स्पष्ट करने वाला है क्योंकि इसने केवल दो योग्यताओं, यानी सीनियर सेकेंडरी और तीन साल के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बीच एक पूर्व-मौजूदा समकक्षता को पहचानने की मांग की। **प्रवीण कुमार सी.पी. बनाम केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य, (2021) 17 सुप्रीम कोर्ट केसेस 383** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील तर्क देंगे कि आदेश को एक समकक्षता को पहचानने और स्वीकार करने के लिए स्पष्ट करने वाला माना जाना चाहिए जो अतीत में पहले से ही मौजूद था लेकिन जिसे गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद योग्यता प्राप्त की। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से बहुत पहले योग्यता थी और एक बार जब प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई योग्यता को सीनियर सेकेंडरी योग्यता के समकक्ष घोषित कर दिया जाता है, तो एक तार्किक परिणाम के रूप में, इसे आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से संबंधित होना चाहिए। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में कोई अवैधता नहीं की कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता पात्र था। जवाब में आगे का तर्क यह है कि 12.10.2015 के आदेश के उद्देश्य को केवल उन लोगों के

लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोलने के उद्देश्यों तक सीमित और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है जिनके पास पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स है, बल्कि भर्ती के उद्देश्यों के लिए भी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश में समकक्षता बनाने के कारण, कोई कारण नहीं है कि इसे भर्ती उद्देश्यों सहित सभी उद्देश्यों के लिए समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थीगण ने लंबे समय से चयन की प्रक्रिया जारी रखी है और यदि इस बीच समकक्षता बनाई गई थी और उन लोगों को जिनके पास समकक्ष योग्यता है, लाभ की अनुमति नहीं दी जाती है, तो समकक्षता देने का बहुत उद्देश्य विफल हो जाएगा।

15. हमने पार्टियों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है और हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

16. यह विवादित नहीं है कि एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 12.02.2013 को जारी किए गए विज्ञापन ने 1996 के नियमों के नियम 273 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में पात्रता मानदंड निर्धारित किया, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। 1996 के नियमों के नियम 273 का एक अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि योग्य बनने के लिए, अन्य आवश्यकताओं के अलावा, एक उम्मीदवार को सीनियर सेकेंडरी पास या उसके समकक्ष परीक्षा की योग्यता रखने की आवश्यकता है। अनुभव की लंबाई के संदर्भ में एक अतिरिक्त योग्यता है जिसका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं। हालांकि, नियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि योग्य बनने के लिए व्यक्ति को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.03.2013 थी और यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर दोनों पार्टियों में से किसी के द्वारा विवाद नहीं है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 30.06.2013 तक कर दिया गया था जो रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत स्थिति है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि एक उम्मीदवार, योग्य होने के लिए, शासी नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार या विज्ञापन में निर्दिष्ट के अनुसार पात्रता मानदंड रखना चाहिए। यदि नियम या विज्ञापन में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले पात्रता मानदंड रखना आवश्यक है। अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के संज्ञान में सही ढंग से उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति को लाया है जैसा कि निर्णयों की प्रचुरता में निरूपित किया गया है।

17. **रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती)** (supra) के मामले में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

"10. यह तर्क कि उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता की जांच चयन की तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए न कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में, इसे केवल अस्वीकार करने के लिए कहा जाना है। चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होती है। ऐसी तारीख के ज्ञान के अभाव में उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे यह बताने में असमर्थ होंगे कि वे प्रश्न में पदों के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उन्हें अभी तक योग्यता प्राप्त करनी है। जब तक विज्ञापन में एक निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं होता है जिसके संदर्भ में योग्यताओं को आंका जाना है, चाहे वह तारीख चयन की हो या अन्यथा, उन उम्मीदवारों के लिए जो वर्तमान में आवश्यक योग्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए भी पदों के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। तारीख की अनिश्चितता एक विपरीत परिणाम भी हो सकती है, अर्थात्, यहां तक कि वे उम्मीदवार जिनके पास वर्तमान में योग्यता नहीं है और भविष्य में उन्हें एक अनिश्चित भविष्य की तारीख में प्राप्त करने की संभावना है, वे भी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आवेदनों की संख्या बढ़

सकती है। लेकिन एक और भी बुरा परिणाम हो सकता है, कि यह कदाचारों के लिए एक गुंजाइश छोड़ सकता है। चयन की तारीख को इस तरह से तय या हेरफेर किया जा सकता है ताकि कुछ आवेदकों का मनोरंजन किया जा सके और दूसरों को मनमाने ढंग से अस्वीकार किया जा सके। इसलिए, विज्ञापन/अधिसूचना में आवेदनों को आमंत्रित करने वाली एक निश्चित तारीख के अभाव में जिसके संदर्भ में अपेक्षित योग्यताओं को आंका जाना चाहिए, योग्यताओं की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तारीख आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब वर्तमान मामले में चयन समिति ने, जैसा कि श्री मनोज स्वरूप ने तर्क दिया है, आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बजाय चयन की तारीख को अपेक्षित योग्यताओं को ध्यान में रखा, तो इसने स्पष्ट अवैधता के साथ काम किया, और इस आधार पर ही प्रश्न में चयन को रद्द करने योग्य है। इस संबंध में इस न्यायालय के दो हालिया निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है *ए.पी. पब्लिक सर्विस कमीशन, हैदराबाद बनाम बी. शरत चंद्र (1990) 2 एससीसी 669 और जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, विदानगरम बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी, (1990) 4 एसएलआर 2371*।"

18. उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

"11. यह इस उद्देश्य के लिए है कि हम भविष्य की चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं:

A. विश्वविद्यालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पदों के लिए जिन योग्यताओं का विज्ञापन करता है, वे उसके अध्यादेश/नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं से भिन्न नहीं होनी चाहिए।

B. चयनित उम्मीदवारों को प्रश्न में पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, या उस उद्देश्य के लिए विज्ञापन/अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लिखित तिथि तक

योग्य होना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा उक्त तिथि के बाद प्राप्त की गई योग्यताओं को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह मनमाना होगा और भेदभाव का कारण बनेगा। यह याद रखना चाहिए कि जब विज्ञापन/अधिसूचना यह दर्शाती है कि उम्मीदवारों के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में या उस उद्देश्य के लिए उल्लिखित विशिष्ट तिथि के संदर्भ में प्रश्न में योग्यता होनी चाहिए, तो जिनके पास ऐसी योग्यता नहीं है, वे पदों के लिए आवेदन नहीं करते हैं, भले ही वे ऐसी योग्यता प्राप्त करने की संभावना रखते हों और उक्त तिथि के बाद उन्हें प्राप्त कर लें। इन परिस्थितियों में, कई लोग जो अन्यथा विचार किए जाने के हकदार होंगे और यहां तक कि जो आवेदन करते हैं उनसे बेहतर भी हो सकते हैं, उनकी एक वैध शिकायत हो सकती है क्योंकि उन्हें विचार से बाहर रखा जाता है।

C. जब विश्वविद्यालय या उसकी चयन समिति न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं में छूट देती है, जब तक कि विज्ञापन/अधिसूचना में विशेष रूप से यह नहीं बताया जाता है कि योग्यताओं में छूट दी जाएगी और साथ ही जिन शर्तों पर उनमें छूट दी जाएगी, छूट अवैध होगी।

D. विश्वविद्यालय/चयन समिति को चयन की अपनी कार्यवाही में प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में छूट देने के कारणों का उल्लेख करना होगा जिसके पक्ष में छूट दी गई है।

E. चयन समिति की बैठकों के मिनटों को पर्याप्त लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, और यदि चयन प्रक्रिया को चुनौती दी जाती है जब तक कि चुनौती का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। यदि मिनट नष्ट हो जाते हैं या यह दलील दी जाती है कि वे उपलब्ध नहीं हैं तो एक प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

19. कानून का उपरोक्त निर्धारण और कानूनी स्थिति यह स्पष्ट करती है कि उम्मीदवार द्वारा नियत तिथि के बाद प्राप्त की गई योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वह मनमाना होगा और भेदभाव का कारण

बनेगा। यह भी उजागर किया गया है कि जब विज्ञापन/अधिसूचना यह निर्धारित करती है कि उम्मीदवार के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में या उस उद्देश्य के लिए उल्लिखित विशिष्ट तिथि के संदर्भ में प्रश्न में योग्यता होनी चाहिए, तो जिनके पास ऐसी योग्यता नहीं है, वे पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, भले ही वे ऐसी योग्यता प्राप्त करने की संभावना रखते हों और उक्त तिथि के बाद उसे प्राप्त कर लें। ऐसी परिस्थितियों में, कई लोग जो अन्यथा विचार किए जाने के हकदार होंगे और यहां तक कि जिन्होंने आवेदन किया है उनसे बेहतर भी हो सकते हैं, उनकी एक वैध शिकायत हो सकती है क्योंकि उन्हें विचार से बाहर रखा जाता है।

20. हालांकि, वर्तमान मामले में जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि उस मामले में क्या होगा जहां चयन की प्रक्रिया के दौरान और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, कोई समकक्षता खींची जाती है जिसका प्रभाव उन व्यक्तियों को योग्य बनाने का होता है, जो समकक्षता खींची जाने के कारण, नियमों या विज्ञापन में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को नहीं रखने के कारण योग्य नहीं थे।

21. इससे पहले कि हम उपरोक्त मुद्दे पर उपरोक्त कानूनी स्थिति की जांच करें, हम यह तय करना उचित समझते हैं कि 12.10.2015 के आदेश का दायरा और क्षेत्र क्या था। इस विवाद की सराहना करने के लिए, उपरोक्त आदेश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा:-

"राजस्थान सरकार
शिक्षा (समूह - 6) विभाग

क्रमांक:-प.3(2) शिक्षा-6/2015

जयपुर, दिनांक:- 12-10-

2015

आदेश

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण के क्रम में विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 04-05-2015 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1- कक्षा-10 की समकक्षता हेतु:-

1- कक्षा-आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा-10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिंदी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

2- उपरोक्त दोनों विषय हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरांत ही कक्षा-10 वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

3- आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (एनसीवीटी) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी, दसवीं की समकक्षता, हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

2- कक्षा-12 की समकक्षता हेतु:-

1- कक्षा-दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

2- यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो। अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

3- दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (एनसीवीटी) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

4- दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

3- संकाय निर्धारण:- बिंदु संख्या 2 के सभी उक्त बिंदुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जाएगा।

(अशोक कुमार गुप्ता)

वरिष्ठ उप शासन सचिव"

22. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश शिक्षा विभाग (राजस्थान सरकार) द्वारा जारी किया गया था। दूसरे, आदेश की शुरुआती पंक्तियाँ दिखाती हैं कि समकक्षता बनाने का उद्देश्य उन लोगों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोलना था जिनके पास सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नहीं थी और 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, लेकिन उनके पास कुछ अन्य योग्यताएं थीं जो उन्होंने 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त की थीं।

12.10.2015 के आदेश के पैरा 2 के उप-खंड (4) में कहा गया है कि जिनके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन साल का मान्यता प्राप्त कोर्स है, जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें आगे के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए 12 वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। उपरोक्त आदेश का शाब्दिक पठन स्पष्ट रूप से यह बताता है कि आदेश का उद्देश्य उन लोगों के लिए आगे की उच्च शिक्षा के रास्ते खोलने और अनुमति देना था जिन्होंने कुछ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए थे लेकिन सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इसमें किसी विशेष पद पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए समकक्षता का उल्लेख नहीं किया गया था, बहुत कम पंचायती राज विभाग में एलडीसी के पद के लिए।

23. अब हम समकक्षता के केवल स्पष्ट करने वाले होने के संबंध में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क से निपटेंगे। ऐसे तर्क पर, यह मामला बनाने की कोशिश की जाती है कि चूंकि यह केवल स्पष्ट करने वाला था, इसलिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता वास्तव में शुरुआत से ही योग्य था, और यह केवल व्याख्या का मामला था।

24. ऊपर दिए गए हमारे विचार के आलोक में, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह प्रकृति में स्पष्ट करने वाला था। 12.10.2015 के

आदेश की सामग्री को प्रकृति में स्पष्ट करने वाला नहीं कहा जा सकता है। दोहराव की लागत पर, हम दोहराते हैं कि आदेश का एक शाब्दिक पठन यह बताता है कि इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए आगे की उच्च शिक्षा के रास्ते खोलना था जिन्होंने कुछ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए थे लेकिन सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इसलिए, यह स्पष्टीकरण का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा समकक्षता बनाने के लिए लिया गया एक बाद का निर्णय है, वह भी एक सीमित उद्देश्य के लिए लेकिन निश्चित रूप से भर्ती के उद्देश्यों के लिए नहीं।

25. **प्रवीण कुमार सी.पी. बनाम केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर रखा गया भरोसा, इसलिए तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी गलत है। उस मामले में, तथ्यों पर, यह पाया गया कि समकक्षता पहले से ही मौजूद थी और भर्ती अधिसूचना में ही परिलक्षित होती थी और यह व्याख्या का मामला था। वास्तव में, ऐसे आधार पर आगे बढ़ते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे **बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि और अन्य बनाम आर्य के. बाबू और अन्य** (सुप्रा) के मामले से अलग किया। इस संबंध में पैराग्राफ 25 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:-

"25. पीके के मामले में रोजगार अधिसूचना के खंड 7 का नोट (v) और एडी के मामले में रोजगार अधिसूचना के खंड 7 का नोट (vi) समकक्षता आदेशों के प्रकटीकरण की आवश्यकता थी। दो जी.ओ. का एक सादा पठन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी डिग्री पात्रता मानदंड में निहित अपेक्षित योग्यताओं के समकक्ष थीं। आर्य के. बाबू में, विवादित विषय को बाद में मान्यता दी गई और पात्रता मानदंड के हिस्से के रूप में पेश किया गया। समकक्षता का सिद्धांत मुख्य तर्क नहीं था जिसके आधार पर उक्त मामले का फैसला किया गया था। "समकक्षता" शब्द का अपने सादे अर्थ में तात्पर्य कुछ ऐसा है

जो दूसरे के बराबर है। शिक्षा के क्षेत्र में, दो विषयों में डिग्रियों के संबंध में समकक्षता के सिद्धांत का अनुप्रयोग का मतलब होगा कि उनका हमेशा एक ही दर्जा या स्थिति थी, जब तक कि समकक्षता देने वाला आधिकारिक साधन उस तारीख को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे संबंधित विषयों को ऐसे ही, स्पष्ट शब्दों में या निहितार्थ द्वारा, माना जाएगा।

26. तर्कों के लिए भी, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान, 12.10.2015 के आदेश के माध्यम से एक समकक्षता खींची गई थी, तो प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को योग्य नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह परीक्षा की मध्यधारा प्रक्रिया में पात्रता मानदंड को बदलने के बराबर होगा। **अंकिता ठाकुर और अन्य बनाम एच.पी. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य (सुप्रा)** के मामले में, लगभग समान परिस्थितियों और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत जहां कुछ पाठ्यक्रमों को समकक्षता प्रदान करने वाला स्पष्टीकरण/छूट आदेश अनुभवजन्य डेटा पर आधारित था कि पाठ्यक्रम मौजूदा नियमों में निर्दिष्ट के समान, या बड़े पैमाने पर समान थे, यह निम्नानुसार नोट किया गया था:-

"49. रिकॉर्ड की जांच करने पर हम यह नहीं पा सके कि कुछ पाठ्यक्रमों को समकक्षता प्रदान करने वाला स्पष्टीकरण/छूट आदेश अनुभवजन्य डेटा पर आधारित था कि पाठ्यक्रम मौजूदा नियमों में निर्दिष्ट के समान, या बड़े पैमाने पर समान, विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न नामांकनों के तहत आयोजित किए जा रहे थे। वास्तव में, स्पष्टीकरण या छूट आदेश क्या करता है कि यह एक निजी संस्थान से प्राप्त कुछ पाठ्यक्रमों/डिप्लोमा को निहित रूप से मान्यता देना शुरू करता है, जैसे कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आईटी कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकृत एक समाज से, यह जांच किए बिना कि मौजूदा सांविधिक शासन के तहत उन्हें मान्यता प्राप्त माना जा सकता है या नहीं।"

उस तथ्यात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए, कानूनी स्थिति इस प्रकार घोषित की गई थी:-

"50. हमारी राय में, यदि मान्यता प्रदान करने के लिए एक सांविधिक प्रक्रिया मौजूद है, तो एक संस्थान को उस प्रक्रिया से बाहर मान्यता प्राप्त नहीं माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1975) 3 एससीसी 76 में आयोजित किया था, समकक्षता का मुद्दा एक तकनीकी मुद्दा है और जहां सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, न्यायालय को हल्के में उसके निर्णय को परेशान नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बाहरी या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित न हो या दुर्भावना से प्रेरित न हो या तर्कहीन और विकृत या स्पष्ट रूप से गलत न हो। लेकिन यह एक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्रियों या प्रमाण पत्रों को निर्दिष्ट के बराबर मानने का मामला नहीं है, बल्कि यह निजी संस्थानों द्वारा आयोजित कुछ पाठ्यक्रमों को मान्यता देने का है, चाहे वे मौजूदा सांविधिक शासन के अनुसार मान्यता प्राप्त हों या नहीं। यह, हमारी राय में, बीच में ही पात्रता मानदंड को बदलने के बराबर है क्योंकि मौजूदा नियमों और विज्ञापन दोनों ने यह निर्धारित किया था कि डिप्लोमा/विशिष्ट पाठ्यक्रम एक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से होना चाहिए। यहां तक कि यह मानते हुए कि मान्यता प्रदान करने के लिए कोई सांविधिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी, पात्रता योग्यता में ऐसी छूट का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए था, और उन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए था जिन्हें बाहर रखा गया था, ताकि वे आवेदन कर सकें और प्रतिस्पर्धा कर सकें, जैसा कि इस न्यायालय ने *बैंक ऑफ इंडिया बनाम आर्य के. बाबू* में आयोजित किया था।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चयन की मध्यधारा प्रक्रिया में समकक्षता को चुपचाप और गुप्त तरीके से कुछ उम्मीदवारों को लाभ देने के लिए काम

नहीं किया जा सकता था, जो पात्रता मानदंड के नंगे पठन पर, योग्य नहीं थे। ऐसे मामलों में, पालन करने के लिए आवश्यक उचित तरीका यह है कि छूट/समकक्षता योग्यताओं का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना आवश्यक है और उन सभी को अवसर प्रदान करना आवश्यक है जो ऐसी समकक्षता के आधार पर योग्य होंगे लेकिन उन्हें बाहर रखा गया था ताकि वे आवेदन कर सकें और प्रतिस्पर्धा कर सकें।

27. विशेष रूप से, बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, कोच्चि और अन्य बनाम आर्य के. बाबू और अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसे प्रवीण कुमार सी.पी. बनाम केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य (सुप्रा) के मामले में अलग किया गया था। तथ्यों पर, योग्यता के मुद्दे पर फिर से विचार आया, जिसमें बी.एससी. (एग्रो-फॉरेस्ट्री) में डिग्री के रूप में आवश्यक योग्यता को दर्शाने वाली एक अधिसूचना 17.11.2014 को जारी की गई थी, जबकि चयन प्रक्रिया 17.09.2015/29.05.2015 को नियुक्ति पत्र जारी होने पर समाप्त हो गई थी। उसमें प्रतिवादी, जो अधिसूचना की तारीख को बी.एससी. (फॉरेस्ट्री) में स्नातक थे, योग्य नहीं थे। हालांकि, बाद में 16.01.2016 को बी.एससी. (फॉरेस्ट्री) की योग्यता को शामिल करके सामान्य शुद्धिपत्र द्वारा परिवर्तन किए गए थे। यह माना गया कि ऐसा समावेश/समकक्षता केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, उस योग्यता रखने वाले सभी लोगों को अवसर प्रदान करके और पूर्वव्यापी प्रभाव से इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह निम्नानुसार देखा गया था:-

"14. यदि मोहम्मद सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (2009) 4 एससीसी 555 में उपरोक्त निर्णय को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि नियोक्ता के कार्य की शुद्धता की जांच करते समय, अधिसूचना में प्रकाशित

योग्यता मानदंड पवित्र होगा, क्योंकि यदि योग्यता मानदंड में कोई बदलाव मध्यधारा में किया जाता है, तो इसे केवल याचिकाकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसे सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खुला किए बिना, यह दूसरों के लिए अन्याय का कारण होगा जिनके पास ऐसी योग्यता है, लेकिन उन्होंने खुद के प्रति ईमानदार होने के कारण आवेदन नहीं किया क्योंकि वे जानबूझकर अधिसूचना में मांगी गई योग्यता नहीं रखते थे, हालांकि उनके पास अन्यथा एक और डिग्री थी। इसलिए, यदि अधिसूचना जारी होने के बाद लेकिन चयन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले योग्यता/मानदंड में कोई बदलाव होता है और नियोक्ता/भर्ती एजेंसी बदलाव को अपनाना चाहती है, तो नियोक्ता के लिए अधिसूचना में बदलावों को शामिल करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी करना और बदले हुए मानदंडों के अनुसार योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित करना और प्रारंभिक अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ उसी पर विचार करना अनिवार्य होगा। जब न्यायालय द्वारा एक विचार किया जाता है तो यही सिद्धांत अच्छा रहेगा।"

28. निष्कर्ष में, अंकिता ठाकुर और अन्य बनाम एच.पी. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांत लागू होगा और वह नहीं जो प्रवीण कुमार सी.पी. बनाम केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किया गया है।

29. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम इस विचार के हैं कि रिट याचिका खारिज होने योग्य थी।

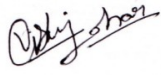
30. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), न्यायाधीश (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव),

मुख्य न्यायाधीश

संजय कुमावत/मोहिता/301

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़